Email id -
seeudc1gzb@gmail.com
CUG Mob.-9193320111
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 1194/ वि0न0वि0म0–प्रथम / गा0बाद

दिनांक 03/08/24

विषयः:–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
पंजाब केसरी, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्द आत्मा, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉक **05.08.2024** तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बडा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्वन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी / अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्वधित वीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर / सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें " का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नकः–विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पत्रांक : 1194 / वि0न0वि0मण्डल–प्रथम / गा0बाद दिनांकः– 03/08/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रवन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0),गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः–propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्वन्धित निविदा पत्रावली।

(अनिल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

सम्पादकीय

मुसीबत की बरसात

बरसात का मौसम हर वर्ष विकराल तबाही के मंजर लेकर आने लगा है। पहाड़ी इलाकों में तो हर वक्त बुरी खबर की आशंका बनी रहती है। अभी तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से जमीन धंसने, घर, पुल, सड़क [illegible] में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लापता हैं [illegible] निकालने की कोशिशें जारी हैं। इसी तरह केरल के वायनाड में भी भारी तबाही हो गई। भूस्खलन में पूरे के पूरे कई गांव दब गए। मरने वालों की संख्या तीन सौ के करीब पहुंच रही है, बहुत सारे लोग लापता हैं। ऐसे में फिर से वही सवाल उठने लगे हैं, जो कई वर्षों से [illegible]। इस मुसीबत की बरसात में सबसे प्रमुख सवाल यह उठ रहा है कि बरसात और उससे होने वाली तबाही को लेकर पहले से चेतावनी जारी करने का कोई भरोसेमंद तंत्र क्यों विकसित नहीं किया जाता, जिससे लोगों को समय रहते जोखिम वाली जगहों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। [illegible] भारी तबाही हो सकती है, मगर [illegible] राज्य सरकार ने ऐसी किसी चेतावनी से इंकार किया है। अब विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि बारिश और भूस्खलन को लेकर पूर्व चेतावनी का व्यावहारिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। बरसात के बारे में चेतावनी मौसम विभाग जारी करता है, मगर अक्सर उसके पूर्वानुमान भरोसेमंद साबित नहीं होते। अनेक ऐसे उदाहरण हैं [illegible] बरसात में होने वाले नुकसान का सही-सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। [illegible] विकास परियोजनाओं के चलते अनेक जगहों पर पहाड़ छिल चुके हैं, उनकी मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है।

ऐसे में तेज बरसात होती है, पहाड़ धसने लगते हैं। उन पर बने घर, सड़कें और पुल ध्वस्त हो जाते हैं। बरसात की प्रकृति भी अब किसी से छिपी नहीं है। [illegible] के गर्म होने से इस मौसम में बादल तेजी से बनते और मोटी बूंदों के रूप में बरसने लगते हैं। बादल फट पड़ते हैं। कम समय में बरसे अधिक पानी को पहाड़ झेल नहीं पाते। वायनाड के बारे में भी तथ्य छिपे नहीं थे। वहां का काफी बड़ा इलाका जोखिमभरा है। मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से वहां भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। मौसम विभाग और भू-सर्वेक्षण से जुड़े महकमे अगर परस्पर तालमेल कर अध्ययन करें, तो बरसात के समय होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। जोखिम वाले इलाकों पर बारीकी से नजर रखी जाए, तो समय रहते वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मगर इसके मद्देनजर न तो विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाता है और न संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से एहतियाती उपाय किए जाते हैं। बरसात के समय हादसे हो जाने के बाद सब सक्रिय नजर आते हैं, जिन्हें राजनीति करनी होती है, वे इस पर राजनीति भी करते हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक अशोक कौशिक द्वारा फाल्गुन बुक्स एंड प्रिन्टर्स ए-1/185 स्वदेशी कॉम्पलैक्स, कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद-201001 से छपवाकर 308 अंसल सुनेहरा बिल्डिंग, आर डी.सी. राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक	:	अशोक कौशिक
समाचार सम्पादक	:	राकेश शर्मा
कानूनी सलाहकार	:	राजकुमार शर्मा, प्रदीप त्यागी, विकास त्यागी
मो.	:	9810149213
फोन	:	0120-4113213
E-mail	:	hindatma@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

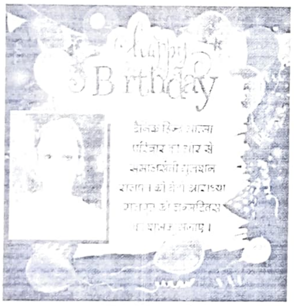

बजट से बाहर रहा पर्यावरण

डॉ. ओ.पी. जोशी

> शहरों में विकास के नाम पर तो जंगलों में विद्युत, रेल, सड़क, बांध एवं खनन कार्य की परियोजनाओं के नाम पर काटे जा रहे हैं। 23 जुलाई को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 2024-25 का 48.21 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया था। बजट के जो नौ आधार कृषि, कौशल-विकास, मानव-संसाधन विकास, मेन्युफेक्चरिंग सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, नवाचार शोध व विकास, ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक सुधार बताये गये, उनमें पर्यावरण की समस्याएं एवं सुधार कहीं नजर नहीं आया। 'केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को दिया गया 3330.37 करोड़ रुपयों का आवंटन देश के बिगड़े पर्यावरण के हालातों के मद्देनजर काफी कम है।

बाढ़-नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु आवंटन 11,500 करोड़ रुपए भी कम ही लगते हैं, क्योंकि बाढ़ से हानि काफी अधिक होती है। शहर एवं बाहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु हरियाली विशेषकर पेड़ बचाना जरूरी है, परंतु पेड़ शहर एवं जंगल दोनों जगह कम हो रहे हैं। शहरों में विकास के नाम पर तो जंगलों में विद्युत, रेल, सड़क, बांध एवं खनन कार्य की परियोजनाओं के नाम पर काटे जा रहे हैं। 23 बाढ़-नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु आवंटित 11,500 करोड़ रुपए भी कम ही लगते हैं, क्योंकि बाढ़ से हानि काफी अधिक होती है। शहर एवं बाहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु हरियाली विशेषकर पेड़ बचाना जरूरी है, परंतु पेड़ शहर एवं जंगल दोनों जगह कम हो रहे हैं। शहरों में विकास के नाम पर तो जंगलों में विद्युत, रेल, सड़क, बांध एवं खनन कार्य की परियोजनाओं के नाम पर काटे जा रहे हैं। 23 जुलाई को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 2024-25 का 48.21 लाख करोड़ रूपयों का बजट पेश किया था। बजट के जो नौ आधार कृषि, कौशल-विकास, मानव-संसाधन विकास, मेन्युफेक्चरिंग सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी-विकास, नवाचार शोध व विकास, ऊर्जा-सुरक्षा एवं आर्थिक सुधार बताये गये, उनमें पर्यावरण की समस्याएं एवं सुधार कहीं नजर नहीं आया। 'केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को दिया गया 3330.37 करोड़ रुपयों का आवंटन देश के बिगड़े पर्यावरण के हालातों के मद्देनजर काफी कम है। संगठन आयक्यूएआर ने इसी वर्ष के प्रारंभ में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 09 हमारे देश के हैं तथा सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 देशों में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। देश की 96 प्रतिशत आबादी प्रदूषित वायु में सांस ले रही है। वर्ष 2019 में देश के 138 शहरों में शुरू किये गये 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' के तहत तय किया गया था कि वर्ष 2024-25 तक 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' (एक्यूआय) घटाकर 50 के लगभग लाया जाएगा। इसी संदर्भ में मार्च 2022 में संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार काफी कम हुआ है, अतः बजट बढ़ाया जाए, कार्य में पारदर्शिता लाएं तथा समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहरों को विकास हेतु 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। ये शहर पर्यावरण को महत्व देकर वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण, जलस्रोतों के संरक्षण, हरियाली विस्तार एवं वर्षा-जल पुनर्भरण पर ध्यान दें तो आदर्श शहर बन सकते हैं। जलस्त्रोत एवं नदियों के विकास के तहत गंगा सफाई हेतु 30033.83 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। बजट में पैसे देने से गंगा साफ नहीं होगी, अपितु इसके प्रदूषण के मूलभूत कारणों को जानकर उन्हें समाप्त करने के प्रयास ईमानदारी से करने एवं करवाने होंगे। अभी हाल ही में 'उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल' की रिपोर्ट देखकर 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण' (एनजीटी) की प्रधान खंडपीठ ने कहा है कि प्रयागराज में तो गंगा का पानी पीने एवं आचमन के योग्य नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार अध्ययन की गई 521 नदियों में से 351 प्रदूषित पाई गईं। इन नदियों के प्रदूषण-स्तर की गणना कर उस हिसाब से बजट में पैसा दिया जाना था। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के संदर्भ में सिंचाई के लिए जल एवं भूमि की उर्वरता पर ध्यान देना होगा। प्राकृतिक खेती में यदि प्रदूषित पानी से सिंचाई की गई तो फिर वह कितनी प्राकृतिक रहेगी? 'राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान (नीरी),' नागपुर ने दो वर्ष पूर्व अध्ययन कर बताया था कि देश की लगभग 30 प्रतिशत भूमि में उत्पादकता समाप्त हो गई है। बाढ़-नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु आवंटित 11,500 करोड़ रुपए भी कम ही लगते हैं, क्योंकि बाढ़ से हानि काफी अधिक होती है। शहर एवं बाहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु हरियाली विशेषकर पेड़ बचाना जरूरी है, परंतु पेड़ शहर एवं जंगल दोनों जगह कम हो रहे हैं। शहरों में विकास के नाम पर तो जंगलों में विद्युत, रेल, सड़क, बांध एवं खनन कार्य की परियोजनाओं के नाम पर काटे जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में रतलाम-खंडवा ब्राडगेज रेललाइन तथा उत्तरप्रदेश में कांवड़ियों के एक मार्ग हेतु क्रमशः 80 हजार एवं 30 हजार पेड़ काटना प्रस्तावित है।

कुछ अन्य कारणों से शहरों एवं जंगलों में पेड़ों की कमी से गर्मी एवं लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिसे वर्ष 2024 में अभी तक महसूस भी किया गया। सिक्किम में लू के दिनों की संख्या दहाई में हो गई है एवं उत्तराखंड की कई नदियां जून में ही उफन गई हैं। हिमालय के पहाड़ी राज्यों में वनों की आग की रोकथाम तथा समावेशी विकास हेतु ज्यादा राशि दी जानी थी। उत्तराखंड में ही नवम्बर 23 से जून 24 तक लगभग 950 आगजनी की घटनाएं हुईं जिससे 4000 हेक्टर के सारे पेड़ जल गए। पर्यटन बढ़ाने के चक्कर में राज्य पहाड़ों की सारी पारिस्थितिक व्यवस्था बिगाड़ चुके हैं जिससे कई स्थानों की हालत जोशीमठ के समान हो गई है। उत्तरप्रदेश सरकार को भी ज्यादा राशि दी जानी थी, क्योंकि वहां की 99.4 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। पर्यावरण सुधार के कई कार्य राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों को करना होता है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से वे भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण का कार्य 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल' के साथ राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय भी करते हैं। अप्रैल 2024 में 'एनजीटी' को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण निकायों में 50 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। पर्यावरण-प्रदूषण से जुड़े कई अन्य विभागों में भी कई पद खाली हैं। कम बजट एवं खाली पदों की स्थिति में पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण कैसे सम्भव होगा?

जाट रिश्ते नाते 11 वां परिचय सम्मेलन की सफलता की जिम्मेदारियों का खाका तैयार

हिन्द आत्मा संवाददाता

गाजियाबाद। पारिवारिक मिलन जाट समाज रजिस्टर्ड के बैनर तले होने वाले आगामी 6 अक्तूबर को वेव सिटी एन आर ग्रांड में होने वाले 11 वें जाट रिश्ते नाते परिचय सम्मेलन की तैयारियों को और पुख्ता करने हेतु संगठन के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी और महामंत्री अरुण चौधरी भुल्लन ने सभी वरिष्ठ संग गहन चर्चा वार्ता कर टीम के सुचारु संचालन हेतु जिम्मेदारी सौंपी। पूर्ण कार्य संचालन हेतु बनाई गई समिति का ब्यौरा निम्नवत है:- अध्यक्ष-राजकुमार चौधरी, महासचिव- अरुण चौधरी (भुल्लन), कोष अध्यक्ष-धर्मेंद्र चौधरी, महिला अध्यक्ष - डॉक्टर सरोज सिरोही, उपाध्यक्ष-संजीव मलिक, उपाध्यक्ष - मनोज चौधरी चिपियाना, उपाध्यक्ष - राहुल चौधरी जटवाड़ा, उपाध्यक्ष - देवव्रत चौधरी, उपाध्यक्ष-सुनील चौधरी कोट गांव, उपाध्यक्ष-भूपेंद्र बाबी गोविंदपुरम, उपाध्यक्ष- अरविंद बालियान, उपाध्यक्ष-विजय पाल चौधरी वसुंधरा, उपाध्यक्ष-जगबीर चौधरी जटवाड़ा, उपाध्यक्ष-नरेंद्र चौधरी पूर्व पार्षद रहीसपुर, उपाध्यक्ष-मोहित चौधरी पूर्व ब्लाक प्रमुख चिपियाना, सचिव/ सह कोषाध्यक्ष- वंदना चौधरी, सचिव- विनीत चौधरी, सचिव/मीडिया प्रभारी -प्रदीप चौधरी, सचिव/संपादक- रतेंद्र तेवतिया, सचिव/भोजन व्यवस्था-दीपक चौधरी, सुरेश चौधरी सचिव-सुभाष चौधरी पार्षद, सचिव-हरवीर चौधरी वसुंधरा, सचिव-नवीन चौधरी, सचिव सुबोध चौधरी नगपुर, सचिव-जय प्रकाश एसडीओ, सचिव-विक्रांत चौधरी, सचिव-देवेंद्र सिंह राठी, सचिव-रॉकी चौधरी गोविंदपुरम, सचिव रविंद्र चौधरी ब्रोंझा, सचिव- संजीव चौधरी वेव सिटी, सचिव-बिट्टू खंजरपुर, युवा अध्यक्ष-नवतेज चौधरी काजीपुरा।

जाट रिश्ते नाते ११वा परिचय सम्मेलन हेतु महिला समिति में महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर सरोज सिरोही ने भी अपनी महिला टीम के अंतर्गत अध्यक्ष-डॉ सरोज सिरोही, महासचिव-रेखा चौधरी, कोषाध्यक्ष-बबीता चौधरी, मीडिया प्रभारी -बबीता/डॉ संजुला चहार, उपाध्यक्ष- करुणा चौधरी, उपाध्यक्ष - सुमन चौधरी, उपाध्यक्ष-सुभद्रा चाहर, सह सचिव-कांति तोमर, सचिव-रीता चौधरी, सचिव -मंजु चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी।

एनसीआरटीसी को प्रतिष्ठित प्लेटिनम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 से किया गया सम्मानित

हिन्द आत्मा संवाददाता

गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को नमो भारत प्रोजेक्ट के लिए [illegible] सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें विश्व अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन के दौरान यह सम्मान एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन (ईईएफ) द्वारा प्रदान किया गया।

[illegible] इस अवसर पर एनसीआरटीसी की ओर से [illegible] ने पुरस्कार ग्रहण किया। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि यह पुरस्कार [illegible] आरआरटीएस परियोजना के माध्यम से [illegible] पर्यावरणीय प्रभाव कम करने हेतु एनसीआरटीसी के योगदान और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल नमो भारत ट्रेन एनसीआर में [illegible]

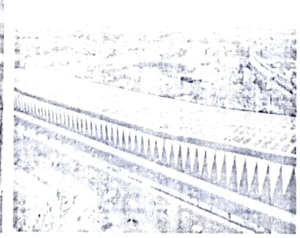

[illegible] बढ़ रही है, क्योंकि [illegible] अधिक सुविधाजनक, विश्वसनीय और [illegible] है। आरआरटीएस [illegible] वायु प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी लगातार बढ़ रही समस्याओं से निपटने के लिए [illegible] समाधानों में से एक है।

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को [illegible] और ऊर्जा-कुशल उपकरण एवं प्रणालियों को लागू करके एनसीआरटीसी पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपना रहा है। नमो भारत ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सतत परिवहन के एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और बिजली द्वारा संचालित होती है। इतना ही नहीं सड़कों पर चलने वाले वाहनों में होने वाली ईंधन की खपत की तुलना में नमो भारत ट्रेनों में महज 1/5 ईंधन की खपत होती है।

एनसीआरटीसी ने आरआरटीएस को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान बनाने की दिशा में कई पहल की हैं, इनमें से कुछ हैं- एनसीआरटीसी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरआरटीएस कॉरिडोर में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। एनसीआरटीसी का लक्ष्य अपने सौर ऊर्जा संसाधनों से सालाना 11 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करना है और इसमें से 3 मेगावाट अक्षय ऊर्जा वर्तमान में पैदा की जा रही है, जिससे सालाना 3,100 टन कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। एनसीआरटीसी द्वारा 11 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सालाना कुल 11,500 टन कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

एनसीआरटीसी द्वारा सभी आरआरटीएस स्टेशनों, डिपो और इमारतों के लिए आईजीबीसी प्रमाणन की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में बेहतर प्रयासों के लिए पहले साहिबाबाद और गुलधर आरआरटीएस स्टेशनों, गाजियाबाद और मुराद नगर रिसीविंग सबस्टेशन और हाल ही में दुहाई आरआरटीएस स्टेशन को प्रतिष्ठित 'प्लेटिनम रेटिंग' अवार्ड प्राप्त हो चुका है।

एनसीआरटीसी ने ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा उपयोग के लिए कई नवीनतम तकनीकों का चयन किया है, जिनमें ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइट, स्टेशनों, रिसीविंग सब-स्टेशनों, एएसएस और डिपो सहित अन्य जगहों पर सोलाट्यूब डेलाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया है। इसके साथ ही नमो भारत ट्रेनों में पुश बटन का फीचर भी खास है, जिसे ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे ट्रेन के सभी दरवाजे एक साथ खुलने के बजाए, चुनिंदा दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ट्रेन में उन्नत प्रकाश व्यवस्था और तापमान नियंत्रण प्रणाली भी यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर तैयार की गई है, जो विद्युत संरक्षण भी सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, एनसीआरटीसी यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक आरआरटीएस स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधाएं भी प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं, एनसीआरटीसी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक भी व्यापक प्रयास कर रहा है, जिसमें जल पुनर्भरण को अधिकतम करने के लिए 900 से अधिक वर्षा जल संचयन गड्ढे विकसित किए जा रहे हैं। यहां तक कि गाजियाबाद और मेरठ जिलों में किसानों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें जल संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली समकालीन कृषि तकनीकों पर जोर दिया गया। किसानों को ड्रिप सिंचाई और हाइड्रोपोनिक्स जैसी आधुनिक कृषि पद्धतियों से परिचित कराकर, एनसीआरटीसी सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है जो उत्पादकता को बढ़ाते हुए पानी की खपत को कम करती हैं। मल्टी-मॉडल एकीकरण भी आरआरटीएस के मुख्य लक्ष्यों में से एक है, जिसका लक्ष्य मौजूदा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ सहजता से जुड़ना है। इसके लिए एनसीआरटीसी ने अन्य परिवहन साधनों के करीब आरआरटीएस स्टेशनों को रणनीतिक रूप से स्थापित किया है, ताकि आरआरटीएस के यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके और सतत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार हो सके। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के सम्पूर्ण रूप से संचालित होने पर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में 37% से बढ़कर 63% की अनुमानित वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इस कॉरिडोर के एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच सड़कों से प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहनों के कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना लगभग 250,000 टन की कमी आने की उम्मीद है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा-13/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर-10000

[illegible] के कार्यालय में नया योजना मद में विद्युतीकरण, पोल शिफ्टिंग संयोजन एवं भार बढ़ाने सम्बन्धी कार्य जो दिनांक 30.08.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संशोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० ए-ब्लाक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक 1194/वि०वि०म०-प्रथम/ग०बाद दिनांक 03/08/2024

राष्ट्रहित में बिजली बचायें।

का फांसी पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने वाले जस्टिस आगा हैदर सहित शहीदों की प्रतिमा एक्शन के प्रतीक रुप में ट्रेन का मॉडल स्थापित करने की पुनः मांग की है। रेल मंत्री को सम्बो अजय कुमार ने आज रेलवे के सहायक मंडलीय अभियंता सुशील कुमार को सौंपा। महापौर ने केंद्र वैष्णव को लिखे पत्र में सहारनपुर के स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रेलवे स्टेशन पर स्थापित करने की अपनी मांग दोहराई है लोकसभा चुनाव के पूर्व भी महापौर ने रेल मंत्री को इस सम्बंध में विस्तार से चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने सैद्धान्तिक रुप से सहमति जतायी थी। उसी संदर्भ में महापौर ने पुनः केंद्रीय रेल मं

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

ई-निविदा-13/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर-10000, वि.न.वि.ख.-पंचम, गा.बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना मद में विद्युतीकरण पोल शिफ्टिंग संयोजन एवं भार बढ़ाने संबंधी कार्य जो दिनांक 30.08.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 बजे खोली जाएगी। किसी भी संशोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है। **हस्ता./-अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण प्रथम,** गाजियाबाद। **"राष्ट्रहित में बिजली बचायें" पत्रांक :** 1194 दिनांक 03.08.2024

उत्तर पश्चिम रेलवे

EOI No.: 6B/M-2/Workplg/xx
दिनांक: 29.07.2024

EOI: कोच केयर सेंटर जोधपुर में लांड्री वॉशर से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करने के बाद पुनः लांड्री वॉशर में उपयोग करने के लिए रिसाइकिल प्लांट लगाना

जोधपुर मंडल (उत्तर पश्चिम रेलवे) के रेलवे लॉन्ड्री जोधपुर के मैकेनिकल विभाग ने इच्छुक पार्टियों से आवेदन मांगे हैं जो लॉन्ड्री वॉशर के डिस्चार्ज पानी को दोबारा लॉन्ड्री वॉशर में इस्तेमाल करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करने के इच्छुक हैं। इस ईओआई का उद्देश्य बाजार मूल्य, प्रक्रिया आदि का आकलन करना है ताकि अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और जल संरक्षण के लिए नवीनतम तकनीकों को शामिल करते हुए उचित प्रस्ताव बनाया जा सके।

इच्छुक पार्टियां अपने ईओआई प्रस्तावों के विवरण के साथ 07.08.24 तक सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू), मैकेनिकल (सी एंड डब्ल्यू) शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर 342001 को भेज सकते हैं।

EOI:
इच्छुक पक्षों द्वारा दिनांक 07.08.2024 को 18:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

(1) कंपनी के लेटर हेड पर कवरिंग लेटर, जिसमें उनके प्रस्ताव को व्यक्त किया गया हो (संपूर्ण नियोजित परियोजना का विवरण (प्रक्रिया और उपयोग की जाने वाली मशीन का पूरा विवरण) प्लांट की कुल लागत के साथ प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख लीटर पानी को रिसाइकिल करना।

(2) आवेदक/फर्म का मूल विवरण

कपड़े धोने की मशीन से निकलने वाले पानी के संभावित मापदंड इस प्रकार हैं:

क्रमांक	कपड़े धोने का पानी आउटपुट पैरामीटर	परीक्षण
1.	PH	9.27
2.	Total Suspended Solids, mg/lit	120.3
3.	COD, mg/lit	412
4.	BOD	300.76
5.	Oil & Grease, mg/lit	6
6.	TDS	2054

धुलाई के उद्देश्य के लिए पुनर्चक्रण के बाद पानी के आवश्यक पैरामीटर निम्नानुसार हैं

पैरामीटर	रेंज
	7-7.5
	Nil

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदा–13/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर–10000, वि0न0वि0ख0–पंचम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना मद में विद्युतीकरण, पोल शिफ्टिंग संयोजन एवं भार बढ़ाने सम्बन्धी कार्य जो दिनांक 30.08.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संसोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम गाजियाबाद
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें''